वर्ष : 33 ▸ अंक : 345 ▸ पृष्ठ : 8 ▸ मुंबई, रविवार, 2 मार्च 2025 ▸ RNI: MAHHIN/49994/91 ▸ मूल्य : 3 रुपए ▸ epaper.dobajedopahar.com ▸ संपादक : अरुण लाल

भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ आजमाने का मौका

▸ पेज - 7

DBD दो बजे दोपहर

पत्रकारिता पावर नहीं रिस्पांसिबिलिटी है

'हमारे लिए ट्रंप का समर्थन पाना जरूरी'

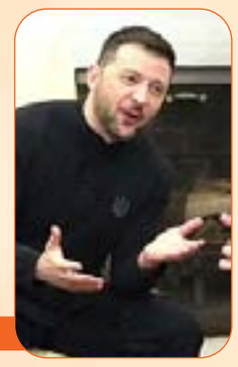

▸ पेज - 8

एक्शन में सीएम फडणवीस

सरकार हुई सख्त, महिला सुरक्षा समेत उठाए कई कड़े कदम

ड्रग्स मामले में मुख्यमंत्री फडणवीस की पुलिस अधिकारीयों को चेतावनी

धर्मेंद्र उपाध्याय । ठाणे

पुणे में हुए दुष्कर्म कांड के बाद महाराष्ट्र सरकार महिला सुरक्षा को लेकर और सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस सम्मेलन में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और नए कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महिला अपराधों पर तेजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अपराधों की तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। जल्द चार्जशीट दायर कर अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जाए। महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। साथ ही सीएम ने अपने मंत्रियों को धैर्य और संवेदनशीलता के साथ बोलने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी राय में मंत्री योगेश कदम ने जो कहा, उसे अलग तरीके से लिया गया।

ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति

राज्य में बढ़ते नशे के मामलों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई पुलिस अधिकारी ड्रग तस्करी या इससे जुड़े किसी अपराध में संलिप्त पाया जाता है, तो उसे तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने नशीली दवाओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार साइबर क्राइम, महिला और बच्चों पर अत्याचार तथा ड्रग तस्करी रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने कठोर कानून का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सम्मेलन में साइबर क्राइम रोकने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

जब्त संपत्तियों को लेकर भी निर्णय

फडणवीस ने कहा कि उद्योगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस को संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, जब्त की गई संपत्तियों को लौटाने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

महाराष्ट्र पुलिस बल देश में सर्वश्रेष्ठ : मुख्यमंत्री फडणवीस

महाराष्ट्र की 35वीं पुलिस खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे में कहा कि यह प्रतियोगिता राज्य पुलिस विभाग के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन अवसर है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अधिक से अधिक पुलिस एथलीटों को इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें।

खिलाड़ियों और महिला भागीदारी की सराहना

मुख्यमंत्री फडणवीस ने महिला खिलाड़ियों की महत्वपूर्ण भागीदारी के लिए विशेष रूप से बधाई दी और कहा कि महाराष्ट्र पुलिस बल को देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास में पुलिस विभाग का योगदान भी सराहनीय है।

'मिशन ओलंपिक' की घोषणा

मुख्यमंत्री ने 2036 ओलंपिक के लिए भारत की तैयारियों के तहत पुलिस एथलीटों को शामिल करने के लिए 'मिशन ओलंपिक' शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पुलिस खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थान प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और राज्य सरकार इसमें हर संभव सहयोग देगी। समापन समारोह ठाणे के साकेत खेल मैदान में आयोजित किया गया, जहां विभिन्न पुलिस खेल टीमों की परेड का आयोजन हुआ। इस अवसर पर महिला और पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ का फाइनल भी आयोजित किया गया।

नेता प्रतिपक्ष पर उद्धव गुट की नजर

- विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर दावा ठोकेगी यूबीटी, राउत ने दिए बड़े संकेत
- एमवीए में सबसे बड़ी है उद्धव की यूबीटी, 3 मार्च से सत्र शुरू

दोपहर संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने एकतरफा निर्णय लेते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता पद पर दावा ठोक दिया है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कोकण क्षेत्र से उद्धव गुट के नेता भास्कर जाधव को विपक्ष के नेता पद की जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन अब खबर आई है कि जाधव को विपक्ष का नेता बनाने का पार्टी के ही विधायकों ने विरोध किया है। इससे शिवसेना (यूबीटी) में घमासान मचने की आशंका प्रबल हो गई है।

विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद उद्धव गुट के पास

जबकि विपक्षी गठबंधन में शामिल कांग्रेस का कहना है कि ऊपरी सदन यानी विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद पहले ही (यूबीटी) के पास है। इसलिए उद्धव विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को दें। या फिर विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद यूबीटी लेती है तो विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद कांग्रेस को दें।

क्या बोले संजय राउत?

शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने 10% सीमा को पूरा न करने के बावजूद महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद का दावा करने की अपनी पार्टी की योजना की घोषणा की है। लगभग 50 विधायकों की संयुक्त विपक्षी ताकत के साथ, राउत स्पीकर की मंजूरी के बारे में आशावादी हैं। राउत ने कहा कि विपक्षी दलों को पहले भी 10% सीट की सीमा को पूरा किए बिना ही यह पद दिया गया है। उन्होंने कहा कि 288 सदस्यीय विधानसभा में संयुक्त विपक्षी ताकत लगभग 50 है।

26 मार्च तक चलेगा बजट सत्र

महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 से 26 मार्च तक चलने वाला है। राउत ने कहा, ₹शिवसेना (यूबीटी) विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा करेगी। भले ही विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन संविधान में ऐसा कोई कानून या प्रावधान नहीं है जो कहता हो कि सदन को विपक्ष के नेता के बिना काम करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी ने यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया है जब विधान परिषद में पहले से ठाकरे गुट के अंबादास दानवे नेता विपक्ष हैं।

दोपहर इन्फो

शिवसेना यूबीटी ने नेता विपक्ष के पद पर भले ही दावेदारी ठोंकी हो लेकिन खबर है कि इसको लेकर अब महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों के बीच ही ठन गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में ही आपस में नही बन रही है।

न्यूज ब्रीफ

मानसून अधिवेशन से ऑनलाइन स्वीकारे जाएंगे जवाब

पुणे। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों को मानसून अधिवेशन से विधायकों के तारांकित और अतारांकित सवालों का लिखित जवाब विधानमंडल सचिवालय को ऑनलाइन देना अनिवार्य होगा। विधानमंडल सचिवालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विधानमंडल सचिवालय के कामकाज को पेपरलेस बनाने की परिकल्पना की गई है। इसके तहत सदन के कामकाज को अधिक से अधिक पेपरलेस बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

कोचिंग संस्थानों पर लगाम की मांग

त्रिची। कोचिंग क्लासेस इंटीग्रेटेड कोर्स चला रहे हैं जहां विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा और ग्यारहवीं, बारहवीं की साथ में तैयारी करते हैं लेकिन यह पूरी शिक्षा व्यवस्था को बर्बादी की कगार पर ले जा रहा है इसलिए कोचिंग संस्थानों पर लगाम लगाने की जरूरत है। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. दीपक सावंत ने शनिवार को शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा के लिए मुंबई में आयोजित 35वें राज्यस्तरीय शैक्षणिक अधिवेशन के दौरान यह बात कही। निजी स्कूलों के संगठन महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडल की ओर से इसका आयोजन किया गया था। डॉ सावंत ने कहा कि अगर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना है तो स्कूलों और महाविद्यालयों को ही पढ़ाई की प्राथमिक जिम्मेदारी संभालनी होगी।

पुणे दुष्कर्म मामला : उपद्रवियों को नहीं बख्शेंगे, पवार ने अख्तियार किया कड़ा रुख

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

धीरज सिंह । पुणे

पुणे में शिवशाही बस में 26 वर्षीय महिला के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने सख्त चेतावनी दी है।

स्वरगेट डिपो तोड़फोड़ मामले की जांच जारी

बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता वसंत मोरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ विरोध-प्रदर्शन के लिए स्वरगेट बस डिपो पहुंचे और वहां तोड़फोड़ की। इस पर अजीत पवार ने कहा, 'अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, तो उसकी भरपाई संबंधित कार्यकर्ता या राजनीतिक पार्टी को करनी होगी। विरोध-प्रदर्शन के लिए तोड़फोड़ करना एकमात्र तरीका नहीं है, इसे शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है।' अजीत पवार की इस चेतावनी पर शिवसेना (यूबीटी) नेता वसंत मोरे ने पलटवार करते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री को केवल तोड़फोड़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि पीड़िता के आत्मसम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने कहा, ₹अगर आप कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करना चाहते हैं, तो बेशक कीजिए, हम डरने वाले नहीं हैं।'

राहुल गांधी को झटका, नासिक कोर्ट में पेश होने का आदेश

दोपहर संवाददाता । नासिक

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान देने के लिए नासिक की एक अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है। नासिक की अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई मई में होगी। अदालत ने राहुल गांधी को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने को कहा है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सावरकर को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में राहुल गांधी को नासिक कोर्ट में पेश करने के आदेश जारी किए गए हैं।

ऑनलाइन पेशी से इंकार

याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने क्या कहा?

आज यानी 1 मार्च को सावरकर अपमानजनक बयान मामले में सुनवाई हुई। हालांकि राहुल गांधी अपने वकीलों के माध्यम से पेश हुए। याचिकाकर्ताओं के वकील मनोज पिंगले के अनुसार, इसलिए अदालत ने राहुल गांधी को ऑनलाइन पेश होने के बजाय अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने और अपना मामला प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर के बारे में अपमानजनक बयान दिया था। राहुल गांधी के बयान से बड़ा विवाद पैदा हो गया था।

कांग्रेस ने अमीन पटेल को बनाया विधानसभा में उपनेता

मुंबई। कांग्रेस ने 4 बार के विधायक अमीन पटेल को महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी का उपनेता और अमित देशमुख को मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। पार्टी ने एक बयान में बताया कि विश्वनाथ कदम को पार्टी के विधानसभा समूह का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि शिरीष नाइक और संजय मेश्राम सचेतक होंगे। कांग्रेस की मुंबई इकाई के वरिष्ठ नेता पटेल मुंबादेवी निर्वाचन क्षेत्र से चार बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 16 रह गई है, जो राज्य विधानसभा में उसकी अब तक की सबसे खराब संख्या है। पार्टी ने राज्य विधान परिषद में सतेज पाटिल को पार्टी नेता नियुक्त किया है और अभिजीत वंजारी को मुख्य सचेतक और राजेश राठौड़ को सचेतक बनाया है।

14 साल तक की लड़कियों को फ्री में दी जाएगी कैंसर की वैक्सीन

दोपहर संवाददाता । पुणे

महाराष्ट्र सरकार ने सेहत के मोर्चे पर बड़ा कदम उठाते हुए 0-14 साल की लड़कियों को मुफ्त कैंसर वैक्सीन देने का ऐलान किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने शनिवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बदलती जीवनशैली के चलते कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, और अब यह बीमारी हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। आबिटकर ने बताया कि राज्य सरकार ने इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए मुफ्त कैंसर वैक्सीनेशन प्रोग्राम लागू करने का फैसला लिया है।

कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ धूम्रपान या अन्य नशे की लत ही जिम्मेदार

रिपोर्ट के मुताबिक, आबिटकर कहा, ₹हमने उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार से अनुरोध किया था कि 0-14 साल की लड़कियों को मुफ्त में कैंसर वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है और जल्द ही सरकार इसे लागू करेगी।₹ बताया जा रहा है कि कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ धूम्रपान या अन्य नशे की लत ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खान-पान और बदलती जीवनशैली भी एक बड़ा कारण बन रही है।

सियासत 2024 लोकसभा चुनाव में 152 सीटों पर नहीं थी कोई महिला उम्मीदवार

महिलाएं मतदान में पुरुषों से आगे, चुनाव लड़ने और जीतने में पीछे

दोपहर संवाददाता । नई दिल्ली

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में भले ही मतदान करने में महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं, लेकिन आजादी के 77 साल बाद भी चुनाव लड़ने और जीतने में काफी पीछे हैं। यहां तक की वर्ष 2024 में हुए चुनाव में लोकसभा की एक चौथाई से भी अधिक सीटों पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। इसका खुलासा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जारी आंकड़ों से हुआ है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक लोकसभा के पिछले दो चुनाव से लगातार महिलाएं, मतदान में पुरुषों से आगे निकल गई हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में 65.78 फीसदी महिला मतदाताओं ने मतदान किया था, जबकि पुरुष मतदाताओं ने 65.55 फीसदी मतदान किया था।

चुनाव लड़ने और जीतने में महिलाएं पीछे

इस जाहिर होता है कि पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं 0 .23 फीसदी अधिक मतदान किया। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिलाएं मतदान करने में आगे रही। ऐसा सिर्फ 2024 के चुनाव में नहीं हुआ, बल्कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मतदान करने में महिलाएं पुरुषों से आगे रही। निर्वाचन आयोग के आंकड़ो से पता चलता है कि 2019 में 67 .18 फीसदी महिला मतदाताओं ने मतदान किया था। जबकि पुरुष मतदाताओं ने 67 .02 फीसदी मतदान किया था।

महाराष्ट्र से सबसे अधिक महिलाएं मैदान में

आजादी के 77 साल बाद भले हीं, महिलाएं मतदान करने में पुरुषों से आगे निकल गई हैं, लेकिन अभी भी चुनाव लड़ने और जीतने में काफी पीछे हैं। वर्ष 1957 में हुए चुनाव में 4 .5 फीसदी महिलाएं चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इस चुनाव में 45 महिलाएं चुनाव मैदान में थी और 22 को जीत मिली थी। जबकि 2024 में 800 महिलाएं चुनव लड़ी और महज 74 जीत पाई। यहां तक की कुल 543 सीटों में से 152 सीटों पर एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक महिलाएं महाराष्ट्र से चुनाव मैदान में थी। महाराष्ट्र से 111, उत्तर प्रदेश 80, तमिलनाडु 77 महिलाएं चुनाव मैदान में थी।

220 लोकसभा पर महिलाएं वोटिंग में थी आगे

चुनाव आयोग ने आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कहा है कि 2024 के लोकसभा आम चुनावों में 220 संसदीय सीटों पर पुरुष मतदाता मतदान की तुलना में महिला मतदाता मतदान (वीटीआर) अधिक था। आयोग ने कहा है कि गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र तीन ऐसे राज्य हैं, जहां पर सभी सीटों पर पुरुष मतदाताओं ने अधिक मतदान किया। आयोग के मुताबिक यह पुरुष और महिला मतदाताओं की भागीदारी पैटर्न में क्षेत्रीय भिन्नता को दर्शाता है, जो विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिशीलता को दर्शाता है।

माणिकराव कोकाटे की सजा पर सस्पेंस बरकरार

अब 5 मार्च को होगी सुनवाई

दोपहर संवाददाता । मुंबई

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे इन दिनों मुश्किलों में है। दस्तावेजों में हेरफेर करके सरकारी कोटे का घर हासिल करने के मामले में मंत्री माणिकराव कोकाटे को मिली दो साल की सजा मिली थी। इस पर जिला अदालत ने रोक लगा दी है। इस पर सस्पेंस शनिवार को खत्म नहीं हो सका। क्योंकि सजा के आदेश को चुनौती देने वाली कोकाटे की याचिका पर शनिवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

शरद शिंदे ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी

अब 5 मार्च को कोर्ट मामले में सुनवाई कर सकता है। जबकि सजा पर रोक की मांग वाली उनकी याचिका के खिलाफ अंजलि दिघोले और शरद शिंदे ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी, जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अंजलि और शरद को तीन दिन में उच्च न्यायालय में अपील करने का सुझाव दिया है।